



COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, AKOLA

**Accredited By NAAC With 'A' Grade
(CGPA 3.27)**

CRITERIA 5

“Student Support and Progression ”

5.1 STUDENT SUPPORT

5.1.4 The Institution has a transparent mechanism for timely readdressed of student grievances including sexual harassment and ragging cases

- 1. Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies*
- 2. Organization wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance*
- 3. Mechanisms for submission of online/offline students' grievances*
- 4. Timely redressal of the grievances through appropriate committees*

Option:

A. All of the above

Proof w.r.t. Organization wide awareness and
undertaking on policies with zero tolerance.

INDEX

Sr No	Particulars	Page No
1	Proof w.r.t. Organization wide awareness and undertaking on policies with zero tolerance	01-48

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2012/ज्येष्ठ 17, 1934

No. 146]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2012/JYAISTHA 17, 1934

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2012

**अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना)
विनियम, 2012**

फा. सं. 37-3/विधि/2012.—तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रवेश में पारदर्शित सुनिश्चित करने तथा अनुचित कार्यों को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करने एवं निर्दोष विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध करवाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा अनुमोदित की गई सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- क) "अभिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;
- ख) "पीडित विद्यार्थी" से अभिप्रेत ऐसे विद्यार्थी से है, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत शिकार के रूप में परिभाषित मामलों में कोई शिकायत है ;
- ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत कोई ऐसी संस्था, चाहे वह उस नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात अभिप्रेत है, जो किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरार, सक्षम माना गया है और जो ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने के लिए परीक्षा आयोजित करती है ;
- घ) "परिषद्" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;
- ङ) "घोषित प्रवेश नीति" से अभिप्रेत शिक्षा के किन्ती भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में प्रवेश देने हेतु बनाई गई ऐसी नीति से है, जिसे परिषद् द्वारा अनुमोदित अथवा मान्यता प्रदान की गई हो एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तथा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाशित किया गया हो।
- च) "शिकायतों" में पीडित विद्यार्थी द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतें शामिल होंगी, यथा :—
 - (i) मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के विपरीत प्रवेश देना ;
 - (ii) संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता ;
 - (iii) संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश देने से इंकार करना ;
 - (iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा उस संस्थान में प्रवेश लेने के उद्देश्य से जमा किए गए उसके दस्तावेज जैसे डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य कोई और प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों को, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी अन्य पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में अध्ययन जारी रखने हेतु उत्प्रेरित अथवा विवश करने के उद्देश्य से रोककर रखना अथवा देने से इंकार करना, किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा शुल्कों को अदा करने के लिए विवश करना ;
 - (v) संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्दिष्ट शुल्क अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक धनराशि की संस्था द्वारा मांग करना ;
 - (vi) प्रवेश में यथा-तानू आरक्षण नीति का उल्लंघन ;

- (vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा विकलांग श्रेणियों के विद्यार्थियों द्वारा की गई भेदभाव बरतने जाने संबंधी शिकायतें ;
- (viii) अमातशिष द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत किसी संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्तियों का भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान करने में देरी करना ;
- (ix) शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट समयानुसार परीक्षाओं के आयोजन में देरी करना अथवा परिणाम घोषित करने में देरी करना ;
- (x) संस्था द्वारा प्रदत्त की जाने वाली अपेक्षित अथवा विद्यार्थियों से वादा की गई सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं करवाना ;
- (xi) प्रवेश के समय वादा की गई अथवा अपेक्षित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने से इंकार करना ;
- (xii) मूल्यांकन का अपारदर्शी अथवा अनुचित तरीका ;
- (xiii) यौन उत्पीड़न सहित, विद्यार्थियों का उत्पीड़न तथा शोषण , तथा
- (xiv) प्रवेश वापस लेने पर, अमातशिष द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, शुल्क की वापसी ।

- छ) "शिकायत निवारण समिति" से अभिप्रेत इन विनियमों के अधीन गठित समिति से है ।
- ज) इन विनियमों के उद्देश्यों से "संस्था" से अभिप्रेत महाविद्यालय अथवा संस्था (जैसा भी मामला हो) से है ।
- झ) "लोकपाल" (आम्बड्समैन) से अभिप्रेत इन विनियमों के खण्ड (3) के उपखण्ड (1) के अधीन नियुक्त लोकपाल (आम्बड्समैन) से है ।
- ञ) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित शिक्षा कार्यक्रमों से है ।
- ट) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित संस्था से है ।
- ड) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसके अंतर्गत ऐसी संस्था भी है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा (3) के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ।

3 शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत नियुक्ति, कार्यकाल, विमुक्ति तथा सेवा की शर्तें :

1. (i) इन विनियमों के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक तकनीकी विश्वविद्यालय लोकपाल (आम्बड्समैन) नियुक्त करेगा ।
- (ii) लोकपाल वह व्यक्ति होगा, जो न्यायधीश (जो जिला न्यायधीश के रैंक से कम का ना हो) रह चुका हो अथवा सेवानिवृत्त प्रोफेसर हो, जिसके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ।

- (iii) विश्वविद्यालय के प्रति लिए जाना यात नियुक्ति की स्वतंत्रता के लिए लोकपाल की नियुक्ति के समय नियुक्ति से एक वर्ष पूर्व अथवा लोकपाल के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के साथ उसका कोई निजी संबंध व्यावसायिक सम्बन्ध अथवा वित्तीय हितलाभ में कोई समझौता अथवा समझौता करने के लिए यथोचित कारण संबंधी कोई विवाद नहीं होना चाहिए।
- (iv) लोकपाल अथवा उनके वर्तमान परिवार का कोई सदस्य निम्नलिखित नहीं होना चाहिए—
- (क) वर्तमान तथा अतीत में विश्वविद्यालय में किसी पद पर नौकरी तथा कोई लाभ याता पद धारण,
 - (ख) विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत संबंध रहित किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण पारिवारिक व्यावसायिक अथवा वित्तीय संबंध,
 - (ग) विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अथवा शासनिक संरचना में किसी भी पदनाम याता पद धारण।
- (v) राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालीन आधार पर निम्नलिखित सदस्यों से बनी खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गये तीन नामों के पैनल में से की जाएगी :—
- (क) संबंधित राज्य के राज्यपाल का नामिती—अध्यक्ष
 - (ख) संबंधित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों से दो कुलपति बारी-बारी से
 - (ग) संबंधित राज्य के निजी विश्वविद्यालयों से एक कुलपति बारी-बारी से
 - (घ) संबंधित राज्य का सचिव (उच्चतर तकनीकी शिक्षा)—संयोजक
- (vi) केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालीन आधार पर निम्नलिखित सदस्यों से बनी खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गये तीन नामों के पैनल में से की जाएगी :—
- (क) अध्यक्ष, अभातशिप—अध्यक्ष
 - (ख) केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों से एक कुलपति बारी-बारी से
 - (ग) संयुक्त सचिव, उच्चतर तकनीकी शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
 - (घ) सदस्य सचिव, अभातशिप—संयोजक
- (vii) लोकपाल एक अंशकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा यह उसी विश्वविद्यालय में एक और समयावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
- (viii) लोकपाल को प्रत्येक सुनवाई के लिए वाहन व्यय के अतिरिक्त समेकित रूप से ₹० 3000 से 5000 का शुल्क दिया जाएगा।
- (ix) लोकपाल को कदाचार अथवा दुर्यवहार के आरोपों के प्रमाणित होने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकता है :

(x) परन्तु हटान का कोई भी आवेदन तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक लोकपाल को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देकर तथा उसको सुनवाई का उचित अवसर देकर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रैंक से कम ना हो इन आरोपों की जाँच न कर ली जाए।

2. तकनीकी संस्था के मामले में, संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित संस्था (ओं) की अपस्थिति (लोकेशन) के ध्यान में रखते हुए संबंधित तकनीकी संस्था से अथवा तकनीकी संस्थाओं के समूह से पौध सदस्य होंगे।

4. लोकपाल (आम्बड्समैन) की शक्तियां एवं प्रकार्य :

- (1) लोकपाल निम्न में से किन्हीं भी शिकायतों को सुनने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा :-

(i) किसी विद्यार्थी द्वारा उस संस्था में उपलब्ध सभी शिकायत निवारण उपायों का प्रयुक्त करने के पश्चात्, विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा उससे संबद्धता प्राप्त संस्था अथवा किसी संस्था, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध की गई शिकायत, तथा

(ii) उस संस्था में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने हेतु कोई भी आवेदक।

- (2) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनःअंकन के लिए दिये गये आवेदनों पर लोकपाल द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें परिणामों को ठोस रूप से प्रभावित करने वाली कोई विशिष्ट अनियमितता अथवा भेदभाव बरतें जाने संबंधी विशिष्ट कारण न हो।

- (3) भेदभाव संबंधी शिकायतों की सौहार्दपूर्ण सुनवाई के लिए लोकपाल को यह अधिकार होगा कि यह भेदभाव संबंधी किसी शिकायत की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग (एस ई बी सी), अल्पसंख्यक अथवा विकलांग श्रेणी से किसी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए अपने साथ रख सकता है।

5. शिकायत निवारण प्रक्रिया :

- (1) प्रत्येक तकनीकी संस्था लोकपाल के निर्णयानुसार, संस्था के एक उपयुक्त पदासीन कर्मचारी के नेतृत्व में एक रजिस्ट्री स्थापित करेगी। जहाँ पर पीडित विद्यार्थी अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण हेतु आवेदन कर सकता है।

- (2) स्थापित की गई इस रजिस्ट्री का पता सूचना पट्ट तथा विवरणिका सहित व्यापक तौर पर प्रचारित किया जाएगा तथा संस्था की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

2057 GI/12-2

- (3) रजिस्ट्री में आवेदन प्राप्त होने पर इसका प्रभारी-कर्मचारी इसके बारे में लोकपाल को सूचित करेगा तथा सात दिन के अंदर इसका उत्तर देने हेतु इसकी प्रति तुरंत संस्था को उपलब्ध करवायेगा।
- (4) लोकपाल शिकायत की सुनवाई के लिए तारीख निश्चित करेगा, जिसकी सूचना पीडित व्यक्ति को तथा संस्थान को लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (जैसा भी संभव हो) दी जाएगी।
- (5) पीडित व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अधिकृत किराये पर प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।
- (6) लोकपाल नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के निर्देशन अनुसार शिकायत की सुनवाई करेगा।
- (7) शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु लोकपाल प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर इसका निपटारा करना सुनिश्चित करेगा।
- (8) तकनीकी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल के साथ सहयोग करेगी। यदि ये ऐसा नहीं करती है, तो इस बारे में लोकपाल द्वारा अभातिषिप को सूचित किया जाएगा।
- (9) शिकायत के निवारण तथा प्रभावित पक्ष को आवश्यक राहत देने के लिए, लोकपाल अपनी कार्यवाही के निष्कर्ष के तौर पर, कारणों सहित उचित समझ जाने वाले आदेश पारित कर सकेगा।
- (10) खण्ड (9) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश, लोकपाल के हस्ताक्षर से पीडित व्यक्ति तथा संस्था को दिया जाएगा तथा ऐसे आदेश तकनीकी संस्था की वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे।
- (11) तकनीकी संस्था के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह लोकपाल के आदेशों का अनुपालन करे।
- (12) लोकपाल के ऐसे किसी आदेश का संस्था द्वारा अनुपालन न किये जाने पर परिषद् द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्यवाई हेतु अभातिषिप को सूचित किया जाएगा।
- (13) शिकायत पीडित विद्यार्थी, उसके माता-पिता अथवा लोकपाल की विशेष अनुमति प्राप्त करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।
- (14) झूठी/निराधार शिकायत के मामले में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई हेतु आदेश दे सकता है।
- (15) सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया की उपरोक्त रूप रेखा, निम्नलिखित को छोड़कर, तकनीकी संस्थान में शिकायत निवारण समिति की कार्य प्रणाली पर लागू होगी —
 (क) एकमतता के अभाव में, शिकायत समिति बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकती है;
 (ख) शिकायत समिति शिकायत प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अपना निर्णय सूचित करेगी।

6. विश्वविद्यालय तथा संबंधित तकनीकी संस्था अपनी विवरणिका में शिकायत निवारण तथा प्रावधानों, लोकपाल तथा विद्यार्थियों के अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में प्रभावता में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएगी।

7. अनुपालन न किये जाने के परिणाम :

परिषद् द्वारा ऐसी किसी भी तकनीकी संस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जो जानबूझकर लोकपाल के आदेशों का अनुपालन नहीं करती अथवा अनुपालन करने में बार-बार असफल रहती है, यथा :

- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं का अनुमोदन) विनियम, 2010 तथा परिषद् द्वारा इसमें समय-समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित किए गए प्रावधानों के अधीन तकनीकी संस्था को प्रदान किए गए अनुमोदन की वापसी अथवा कोई अन्य कार्रवाई अथवा जुर्माना ,
- (ख) परिषद् द्वारा प्रदान की गई फिटनेस की घोषणा को वापस लेना अथवा अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्रता अथवा परिषद् द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय सहायता को वापस लेना ,
- (ग) तकनीकी संस्था को आबंटित किए गए किसी अनुदान को रोकना ,
- (घ) परिषद् के वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले किसी भी सामान्य अथवा विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु विचार करने के लिए तकनीकी संस्था को अपात्र घोषित करना ,
- (ङ) प्रवेश के लिए सभावित विद्यार्थियों सहित जन साधारण को समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से नोटिस प्रकाशित करके अथवा अन्य उपयुक्त संचार माध्यम से तथा परिषद् की वेबसाइट/वेबपोर्टल पर घोषणा करके यह सूचित करना कि तकनीकी संस्था के पास शिकायत निवारण हेतु न्यूनतम मानक उपलब्ध नहीं है ;
- (च) संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को संस्था की सयद्धता वापस लेने हेतु सिफारिश करना ,
- (छ) राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निर्गमित तकनीकी विश्वविद्यालय के मामले में संगत राज्य सरकार को उसके द्वारा प्रदान किए गए उक्त विश्वविद्यालय के दर्जे को वापस लेने की सिफारिश करना ,
- (ज) परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालनार्थ, परिषद् तकनीकी संस्था पर उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी ही अन्य कोई कार्रवाई कर सकती है तथा उस विशिष्ट समयावधि के दौरान अमातशिप अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अधीन ऐसे ही अन्य जुर्माने लगा सकती है :

परंतु संस्था को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किये बिना तथा संस्था को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अमातशिप द्वारा इस खंड के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. ये विनियम, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित कार्यों पर रोक लगाने हेतु अधिनियम के लागू होने पर उपलब्धित रूप में निरसित होंगे।

डी. के. पी. आर्चबैक, सहाय सचिव

[विज्ञापन II/4/131/12/असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2012

All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulations, 2012

F. No. 37-3/Legal/2012.—In order to ensure transparency by Technical institutions imparting technical education, in admissions and with Paramount Objective of preventing unfair practices and to provide a mechanism to innocent students for redressal of their grievances, In exercise of the power conferred under Clause 1 of Section 23 of the All India Council for Technical Education, Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely :

1. **SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT :**

- (1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulations, 2012.
- (2) They shall apply to every Technical Institution recognized or approved by the All India Council for Technical Education under the All India Council for Technical Education Act, 1987.
- (3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **DEFINITION :**

- (1) In these regulations unless the context otherwise requires –
 - a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;
 - b) "Aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances as defined under these regulations;
 - c) "College" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;
 - d) "Council" means the All India Council for Technical Education;
 - e) "Declared Admission Policy" means such policy for admission to a course or programme of study as may be approved or recognized by

the Council and offered by the institution and published in such manner as the council may specify;

- f) 'Grievances' may include the following complaints of the aggrieved students namely -
- (i) making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institute;
 - (ii) irregularity in the admission process adopted by the institute;
 - (iii) refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institute;
 - (iv) withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue;
 - (v) demand of money in excess of that specified in the declared admission policy or approved by the competent authority to be charged by such institution;
 - (vi) breach of the policy for reservation in admission as may be applicable;
 - (vii) complaints of alleged discrimination by students from Scheduled Caste, Scheduled Tribes, OBC, women, minority or disabled categories;
 - (viii) non payment or delay in payment of scholarships to any students that such institution is committed, under the conditions imposed by AICTE, or by any other authority;
 - (ix) delay in conduct of examinations or declaration of results beyond that specified in the academic calendar;
 - (x) on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
 - (xi) denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
 - (xii) non transparent or unfair evaluation practices;
 - (xiii) harassment and victimization of students including sexual harassment, and
 - (xiv) refund of fees on withdrawal of admissions as per AICTE instructions from time to time.
- g) 'Grievance Redressal Committee' means a Committee constituted under these Regulations;
- h) "institution" for the purposes of these Regulations, means, college or institution as the case may be;
- i) "Ombudsman" means such Ombudsman appointed under sub-clause (1) of clause (3) of these Regulations;

20.57 51/12-3

- j) "Technical education" means programs of education as defined under section 2[g] of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;
- k) "Technical Institution" means an Institution as defined under section 2[h] of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;
- l) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under section 3 of the UGC Act 1956.

3. **APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES UNDER REDRESSAL MECHANISM**

- 1. i) Each Technical University shall appoint an Ombudsman for redressal of grievances of students under these regulations.
- ii) The Ombudsman shall be a person who has been a judge not below the rank of a District Judge or a Retired Professor who has at least 10 years experience.
- iii) The Ombudsman shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his tenure as ombudsman, be in a conflict of interest with the university where his personal relationship, professional affiliation or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement toward the university.
- iv) The Ombudsman, or any member of his immediate family shall not :
 - a) hold or have held at any point in the past, any post, employment in office of profit in the University,
 - b) have any significant relationship including personal, family, professional or financial, with the university,
 - c) hold any university position, called by whatever name, under the administration or governance structure of the university.
- v) The Ombudsman in a State Technical University shall be appointed by the University on a part time basis from a panel of three names suggested by the search committee consisting of the following members :
 - a) Nominee of the Governor of concerned State - Chairman
 - b) Two Vice Chancellors by rotation from Public Universities of the State concerned
 - c) One Vice Chancellor by rotation from Private Universities of the State concerned
 - d) Secretary (Higher Technical Education) of the State concerned- Convenor
- vi) The Ombudsman in a Central Technical University shall be appointed by the Central Technical University concerned on a part time basis

from a panel of three names suggested by the search committee consisting of the following members

- a) Chairman AICTE - Chairman
 - b) One Vice Chancellor from Central Technical Universities by rotation
 - c) Joint Secretary Higher Technical Education, MHRD, Government of India
 - d) Member Secretary AICTE - Convenor
- vi) The Ombudsman shall be a part time officer appointed for a period of three years or till 70 years of age whichever is earlier from the date he resumes the office and may be reappointed for another one term in the same university
- viii) Ombudsman shall be paid a consolidated fees of Rs. 3000 to 5000 per hearing, in addition to the conveyance
- ix) The Ombudsman may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior by the concerned appointing authority:
- x) Provided that no order of removal shall be passed except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of High Court Judge in which such Ombudsman has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

2. In case of Technical Institution, the Vice Chancellor of the affiliating university shall constitute a grievance redressal committee consisting of five members for an Individual Technical Institution or a group of Technical Institutions, keeping in view the location of the Technical Institution(s) concerned.

4. **POWERS AND FUNCTIONS OF OMBUDSMAN :**

- (1) The Ombudsman shall exercise its powers to hear any grievance -
- (i) of any student against the university or institution affiliated to it or an institute, as the case may be, after the student has availed of remedies available in such institution for redressal of grievance; and
 - (ii) of any applicant for admission as student to such institution.
- (2) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsman unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated.
- (3) The Ombudsman shall have power to seek the assistance of any person belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Socially and economically backward classes (SEBC) minority or disabled category, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.

2057 67/12-4

5 **PROCEDURE IN REDRESSAL OF GRIEVANCES :**

- (1) Each Technical institution shall establish a registry, headed by an employee of the institute of appropriate rank as the Ombudsman may decide, where an aggrieved student or person may make an applicant seeking redressal of grievance.
- (2) The address of the registry so established shall be published widely including on the notice board and prospectus and placed on the website of the institution.
- (3) On receipt of an application by the registry, the employee-in-charge shall inform the Ombudsman and shall immediately provide a copy to the institution for furnishing its reply within seven days.
- (4) The Ombudsman shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the Institute and the aggrieved person either in writing or electronically, as may be feasible.
- (5) An aggrieved person may appear either in person or represented by such person as may be authorized to present his case.
- (6) The Ombudsman shall be guided by principles of natural justice while hearing the grievance.
- (7) The Ombudsman shall ensure disposal of every application within one month of receipt for speedy redress of grievance.
- (8) The Technical institution shall be expected to co-operate with the Ombudsman in redress of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsman to AICTE.
- (9) On the conclusion of proceedings, the Ombudsman shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue.
- (10) Every order under clause (9), under the signature of the Ombudsman, shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the Technical institution.
- (11) The Technical Institution shall comply with the order of the Ombudsman.
- (12) Any order of the Ombudsman not complied with by the institution shall be reported to the AICTE for appropriate action as deemed fit by the Council.
- (13) A complaint shall be filed by the aggrieved student, his / her parent or with a special permission from the ombudsman, by any other person.
- (14) In case of any false/frivolous complaint, the ombudsman may order appropriate action against the complainant.
- (15) The principles and procedures outlined above shall apply to the working of the Grievance Redressal Committee in the Technical Institute except
 - (a) in case of lack of unanimity, the Grievance Committee shall take decisions by majority;
 - (b) the Grievance Committee shall communicate its decisions within ten days of receipt of complaint.

6. The University and the Technical Institution concerned shall provide detailed information regarding provisions of grievance redressal mechanism, ombudsman and the duties and rights of students in their prospectus prominently.

7. **CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE :**

The Council shall in respect of any Technical Institution that willfully contravenes or repeatedly fails to comply with orders of the Ombudsman, may proceed to take one or more of the following actions, namely;

- (a) Withdraw the approval granted to the Technical Institution or any other action or penalty as provided under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulation, 2010 as modified or amended by the Council from time to time;
- (b) withdrawal of declaration of fitness or entitlement to receive grants or financial assistance from the Council;
- (c) withholding any grant allocated to the Technical institution;
- (d) declaring the Technical institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Council;
- (e) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website/web portal of the Council, declaring that the Technical Institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (f) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation;
- (g) recommend to the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a Technical university established or incorporated under a State Act;
- (h) taking such other action within its powers as the Council may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the Technical institution complies with the provisions of these Regulations ;

Provided that no action shall be taken by AICTE under this clause unless the technical institution has been asked to explain its position and opportunity of being heard has been provided to it.

8. These regulations shall stand impliedly repealed on coming into force of the Prohibition of Unfair Practices in Technical, Medical Educational Institutions and Universities Act.

Dr K. P. ISAAC, Member Secy

[ADVT. III/4/31/12/Exty.]

SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY GAZETTE - 2019 - PART ONE - 474

Regulation No. 17 of 2019

Procedure of Grievances Committee

The Maharashtra Public Universities Act, 2016, came into existence and so it has become expedient to amend/ Frame the regulation of procedure of Grievances committee. The management council is hereby, pleased to make the following Regulation-2019, **Procedure of Grievances Committee.**

1. This regulation may be called as Regulation for Procedure of Grievances Committee-2019.
2. This regulation shall come into force with effect from the date of it's approval by the Management Council.

3. In this regulation unless the context otherwise requires : -

- i. "Grievances Committee" , means the Grievances Committee constituted under sub section (3) of section 79 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- ii. "Teacher " means a Teacher as defined under sub-section (61) of Section 2 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- iii. " University Teacher" means a Teacher as defined under sub-section (68) of Section 2 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- iv. "Management Council" means the Management council constituted under sub section (4) of section 30 of Maharashtra Public Universities Act,2016.
- v. "Other employees" means, other employees working on sanctioned posts of the University, affiliated colleges, institutions and recognized institutions.
- vi. "University" means, Sant Gadge Baba Amravati University established by the Amravati University Act, 1983.
- vii. "Colleges, institution and recognized institution" means college, institution and recognized institution as defined under sub-section (12),(34) & (46) respectively of Section 2 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- viii. "Director" means Director as defined under sub-section (25) of section 2 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- ix. "Management" means Management as defined under sub-section (37) of section 2 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- x. "Principal" means Principal as defined under sub-section (44) of section 2 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.

4. Jurisdiction:-

- i. The Grievances Committee shall have jurisdiction to entertain, hear, settle and decide the grievances of the teachers and other employees of the University, affiliated and autonomous colleges and recognized institutions, which are within the jurisdiction of the University.
- ii. The Grievances Committee shall entertain , hear, settle and decide the grievances only from individuals, no collective complaints shall be entertained.

5. Procedure of filing application/ complaint:-

- i. The complainant shall have to submit his grievance along with the prescribed fees of Rs. 500/- (Rs. Five hundred only) or the fees as decided by the competent authority, from time to time.
- ii. (a) Every complainant shall submit his complaint in 10 copies (one original and 09 attested copies). The complainant shall forward his complaint to the University Office through the University Registrar, Principal/Director of the College / Recognized Institution as the case may be. The complainant may forward one advance copy directly to the University in addition to the 10 copies. It shall be the responsibility of the University Registrar/Principal/Head of Recognized Institution to forward the complaint of the complainant to the University Office along with his say within eight days from the date of receipt of the complaint. Failure to forward the complaint along with his say within this time limit shall be treated as a failure of his duties and responsibilities as per relevant Statutes.

- (b) In case the complainant is Principal/Director, he/she shall submit his/her complaint to the University Office through the Secretary of the management of the College/ Recognized Institution. It shall be the responsibility of the Chairman/Secretary of the Management to forward the complaint along with his/her say to the University within eight days from the receipt of the complaint. Failure to forward the complaint along with their say within the stipulated time limit shall be treated as breach of code of conduct for the management prescribed by the relevant Statutes.
 - iii. In case of failure in forwarding the say within 15 days, Grievances Committee will proceed the matter on the basis of merits of the case.
 - iv. The complainant shall attach attested photo copies of all such documents, which he deems necessary to support his complaint.
 - v. Complaint received in 10 copies along with prescribed fee, shall be placed before the Grievances Committee as expeditiously as possible for taking decision regarding tenability of the Grievances/complaint.
 - vi. The Grievances Committee shall, after due scrutiny of complaint, decide whether the given complaint can be admitted and record it's reasons for it's decisions. On admission of the Grievances/ complaints, it shall be registered in the Office & shall be allotted the Case No. (Pages of the registered complaint shall be numbered as 1,2,3,4 as in chronological order.)
- 6. **Place of seating:** - The Grievances Committee shall meet on any convenient day as decided by the Chairman at such place provided by the University.
- 7. **Language of Grievances Committee:-**
The aggrieved employee may file his application /complaint in Marathi/Hindi/English Language.
- 8. **Powers of Grievances Committee:-**
 - i. Grievances Committee shall have the power to call for record, proceeding and any document in the custody of respondent for its own verification and to verify authenticity of the grievance of the aggrieved employee.
 - ii. The Grievances Committee shall be vested with powers to make decision of grievance of aggrieved employee and for taking appropriate action against party/parties for implementation of its decision.
- 9. **Limitation:-**
The Aggrieved employee shall file his/her appeal/ representation within three months from the date of final order made in connection with his/her complaint. The committee may in exceptional circumstances condone the said period.
- 10. **Subject of Complaints :-**
The Grievances Committee shall entertain, hear, settle and decide the grievances/ complaints as prescribed under the Maharashtra Public Universities Act, 2016.
- 11. **Procedure of the Grievances Committee :-**
 - i. The Grievances Committee shall entertain the complaint and direct both the parties to remain present before the Grievances Committee in its meeting. If both the parties are absent without any valid reasons, then the complaint shall stand dismissed. If one of the parties remains present, the Grievances Committee shall take ex-party decision & this decision shall be binding on both the parties. The complaint once dismissed shall not be re-entertained.
 - ii. Notwithstanding anything contained in this regulation, the complainant and the respondent shall personally, remain present before the Grievances Committee for hearing. They shall not be allowed to send any representative to plead their case before Grievances Committee.

SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY GAZETTE - 2019 - PART ONE - 476

- iii. Every complainant and the respondent shall personally remain present before the Grievances Committee at their own costs.
 - iv. The Grievances Committee shall hear the Grievance of the complainant. While doing so, full opportunity of being heard will be given to both the parties. After hearing both the parties, the Grievances Committee may give hearing to the individual concerned, to explain his grievance personally in its meeting.
 - v. In case of difference in opinion amongst members & Chairman regarding decision of complaint majority rule shall prevail.
 - vi. If the University/Principal/Director/Management as the case may be fails to comply with the decision by the Grievances Committee as provided in subsection (6) of section 79 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 within the period prescribed by the Grievances Committee, then the University/Principal/Director/Management shall be penalized in the following manner:
 - a) If the University/Principal/Director/Management fails to comply with the decision of the Grievances Committee in prescribed time, then the fine of Rs. 1000/- shall be imposed on the defaulter for the first offence for the second & subsequent offences, fine may be increased.
- 12. Save as otherwise as provided hereinabove, the Chairperson shall have discretionary powers to take appropriate action for proper functioning of the Grievances Committee.**
- 13. The "Rule No. 13 of 2010" stands repealed.**

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 81-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के तहत अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ— (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से ये लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ— इन विनियमों में—बशर्त विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी काम के स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है,

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "चरित्र" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र कैंन्ड, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपरानों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैंटीन, बैंक घाटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दीरा किया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय प्रमण हेतु

संस्थान पर, अध्ययनी, अध्ययन समूह, सैर-सपाटे में लिए, लघु-अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिपिंग के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक सम्बरोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है—यह समस्त उस परिवार में सम्मिलित हैं।

(डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है।

(ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना—अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है।

(एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से पद्धतार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन-सहायक, शोध-सहायक याहों से संज्ञा में हैं अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु-सत्र के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है।

(जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, याहों जिस नाम से वे जाने जाते हों— तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सर्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केंद्रीय नागरिक सेवाओं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसमें सम्मिलित नियमों में दर्शाया गया है।

(एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचईआई) से अर्थ है—एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जी) के अन्तर्गत जहाँ से अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (डी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है।

(आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आईसीसी) (इन्टरनल कमप्लेन्ट्स कमिटी) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एल.टी.ए.एल.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बंध्य होगा।

(जे) "सुरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तत्काल विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है— जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में बाधित करने, किसी भी आन्तरिक जांच प्रक्रिया में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न मामलों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया में अथवा किसी मुकदमे में बर्तार गवाह मौजूद रहना।

(के) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है—

(i) ऐसा एक अनवांछ आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो सकती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिशूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अस्वीकृत की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अपेक्षित काम या व्यवहारों में कोई भी एका या उससे अधिक या वे समस्त व्यवहार शामिल हैं (याहों सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः—

(अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अग्रिम शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरेकता कोई आचरण

(ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना

(स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना

- (द) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पारा बन रहने की कोशिश करना
- (ई) अश्लील साहित्य दिखाना
- (ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्तान के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं—
- (अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वाद्य जो लैंगिक सम्बंधन के एवज में है;
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;
- (स) संबद्ध व्यक्ति के बर्तान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;
- (द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;
- (ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;
- (एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विशिष्ट प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हैं
- बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है— यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा;
- बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;
- (एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है—बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;
- (ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल है:
- (अ) कोई विभाग, संगठन, संपन्न, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियंत्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र जहाँ वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में वातावरण शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे प्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।

3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के बाधित—(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)

- (अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;
- (ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अभिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना;

- (स) जैसा कि आयोग की "सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम) रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यमालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुग्राही बनाना तथा इस अभिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित करना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;
- (द) इस बात को महसूस करते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा सीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग अन्वर्षित हिंसा के विरुद्ध निर्णायक रूप से सक्रिय बनना;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;
- (एक) सभी स्तरों पर अपने परिसर बौ, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;
- (जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है— तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;
- (एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नोटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी संसुदायी के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी अर्थ के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेन्डर सेन्सिटाइजेशन कमिटी अगैस्ट सेक्सुअल हार्सेमेंट—जी.एस.सी. ए.एस.एच. निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटी—आई.सी.सी.) के समान ही पुनर्गठित करना;
- बराबरी, बाद में दर्शाते हुए मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा;
- (आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;
- (जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- (के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से गतिशील बनाना चाहे वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी अनिष्ट भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान की योगात्मक टीमों से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो;
- (एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना तथा विधि द्वारा नान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अवरोध हेतु तन्त्र एवं समन्धान प्रणाली को यथार्थस्थिति बनाना;
- (एम) यदि उस दुराचार का धड़यंत्रकारी यहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;
- (एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्मक नियमों (जी बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;
- (ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;
- (पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;
- (क्यू) एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, वह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ—

- (1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केंद्र (आई.सी.सी.) प्रकाश करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय-समय पर संशोधित किया

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुरार अधिनियम लागू किया जाना है।

- (2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकाय के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अपसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सहाय एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आवंटन भी हो।
- (3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से समर्थ से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
- (4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टरेल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं।
- (5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की श्रमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एमआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनर्रचना पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विहंगम रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी स्कान" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविष्टियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक माघदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएं नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए।
- (8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक प्लमर्सदाता होने चाहिए।
- (9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विद्यालय परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अमुरी है तथा अन्य संस्थाओं के लोगों के अनुभव अनुसार ये स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है।
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए।
- (11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के कक्ष जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से ये स्थान जिन तक पहुँच घातक दैनिक भोधाकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शान के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा नरोसेनंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
- (12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रवासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रवास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा हस्तुका युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है।

- (13) पुष्प छात्रों की सुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को मेदनाप पूर्ण नियमों का अन्वय नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करनी— विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए;
- (14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें होनी अनिवार्य है। महिलाओं के विषय में इस प्रक्रिया में लिंग संवेदी डॉक्टर और नर्स तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए;
- (15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकॉष्ठ पुनः शुरू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और उन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकाशों से युक्त करके स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही वे आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के प्रारम्भ से अपनी गतिविधियों विस्तारित करेंगे जिनमें लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियों परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगे। "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल" उन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि वे कार्यशालाएँ नवीम्बरी, आकर्षक बनें एवं मशीनी न हों;
- (16) छात्रावासों के बर्हन अध्यक्ष, प्राचार्य, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अन्तर्गत अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जबाबदेही के दायरे में गणनाअवश्यक रूप से लाना चाहिए;

4. शिकायत समन्धान तन्त्र:-

- (1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदीकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.टी.) का गठन करेंगे। आई.सी.टी. की निम्न संरचना होगी:-
 - (अ) एक पीठासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह-प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो।
बशर्त यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को सप-अनुभाग 2(अ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगा:
"बशर्त यदि इस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियोजन के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"
 - (ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर-अध्ययनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए;
 - (स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;
 - (द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी सभा में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का ज्ञानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- (2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए;
- (3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, प्रदेन कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसे केन्द्र के प्रचारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे;

- (4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करे जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केंद्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;
- (5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य नैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है;
- (6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि—

- (अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
- (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा
- (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी संचालन निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;

तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार मरा जाएगा।”

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :- आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अध्यक्ष छत्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
 - (ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराया ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को सन्नीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण किया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दम्भात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;
 - (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा;
 - (द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या नवार्तों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
 - (ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्रवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अध्यक्ष छत्र एक संरक्षित नतिविधि में व्यस्त है।
6. शिकायत करने एवं जीव पड़ताल की प्रक्रिया:- आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जीव पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे,
7. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :- किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करे।
- बशर्त जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा,
- बशर्त, इसके साथ ही आई.सी.सी., लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर समय सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु यह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आवश्यक किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था,

8. जीव पड़ताल की प्रक्रिया:-

- (1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी;
- (2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पत्तों के नामों एवं उनके पत्तों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा;
- (3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जीव गड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुसूचकों सहित, यदि वे हों, तो, जीव गड़ताल रिपोर्ट उस जीव के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को अस्तुतः की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के सम्मेलन इस जीव के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी;
- (4) जीव रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जीव के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो;
- (5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों/अनुसूचकों के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के सम्मेलन की गई अनुसूचकों की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है;
- (6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है— उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के प्रस्ताव दी आगे की कार्यवाही करेंगे;
- (7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक सम्पत्ति नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथास्थिति उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलभ कराएगा। किसी भी दण्डनीय प्रस्ताव की सुलह में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है;
- (8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जीव प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा;

9. अन्तरिम समाधान:— उच्चतर शैक्षिक संस्थान,

- (अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जोखिम कम से कम बना रहे;
- (ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर शब्धी एवं अन्य हित सानों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश रक्षीकृत कर दे;
- (स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दे;
- (द) सुनिश्चित करे कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिरोध एवं उत्पीड़न से मुक्ति प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए;

10. दण्ड एवं हरजाना:—

- (1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;
- (2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए— यदि प्रतिवादी कोई शिक्षक है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थान—
- (अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे—पुस्तकालय, सभागार, आवासीय जागारों, कक्षागत छात्रवृत्ति, नर्तन एवं महान पत्र आदि तक पहुँच बनाता;

- (ब) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;
- (स) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसी नहीं होगी;
- (द) अतिदोषात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;
- (3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा—
 - (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुःख पहुँचा है;
 - (ब) उस जैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;
 - (स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोसंग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए विकिरित व्यय;
 - (द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
 - (ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुष्ट रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाई—

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य, ध्वे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का अन्तार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार छानबीन की जानी चाहिए।

12. गैर अनुपालन के परिणाम—

- (1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक बिन्दुओं पर कार्यवाई करेगा—
 - (अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आह्वन किया जाना;
 - (ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;
 - (स) संस्थान को आबंटित किसी भी अनुदान को रोक देना;
 - (द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;
 - (ई) जन साधारण को, एवं रोजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा चपसुक्त मीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति मानव जवसमत्तदधम अवसमत्तदधम का समर्थन नहीं करता है;
 - (एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्बद्धता को आह्वित करने की अनुज्ञा के लिये कहें;

- (जी) यदि यह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आदेशों की अनुसंधान करना;
- (एच) यदि यह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आह्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथाशक्ति रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;
- (जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्यवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनको सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन-III/4/असा/53]

जसपाल एस. सैयु. सचिव, गूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
 - (b) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
 - (c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets; student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short- term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;
- Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) "sexual harassment" means-

(i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely:-

- (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
- (b) demand or request for sexual favours;
- (c) making sexually coloured remarks
- (d) physical contact and advances; or
- (e) showing pornography"

(ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-

- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
- (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
- (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
- (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
- (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;

- (i) "student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI;
 Provided that a student who is in the process of taking admission in HEI's campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student;
 Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;
- (ii) "Third Party Harassment" refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose/reason;
- (iii) "victimisation" means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;
- (iv) "workplace" means the campus of a HEI including—
- (a) Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;
 - (b) Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;
 - (c) Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIs.

3. Responsibilities of the Higher Educational Institution- (1) Every HEI shall,—

- (a) Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;
- (b) publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure their wide dissemination;
- (c) organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;
- (d) act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
- (e) publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
- (f) reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
- (g) create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
- (h) include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;

Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 Supportive measures.—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.

(6) All Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCs)) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.

(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.

(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.

(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.

(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.

(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.

(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women's hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.

(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.

(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.

(15) The Women's Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.

(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendment in the rules or Ordinances where necessary.

4. Grievance redressal mechanism.—(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;”

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, **if the matter involves students**, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
- (2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
- (3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
- (4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
- (5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
- (6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee;
- contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
 - has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
 - he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
 - has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.”

5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) - The Internal Complaints Committee shall:

- (a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;

- (b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
- (c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender;
- (d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
- (e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.

6. **The process for making complaint and conducting Inquiry** – The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy.

7. **Process of making complaint of sexual harassment** – An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing.

Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period."

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental incapacity or death.

8. **Process of conducting Inquiry**– (1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.

(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.

(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.

(4) The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.

(5) An appeal against the findings or recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.

(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.

(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. **Interim redressal**-The HEI may,

- (a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
- (b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
- (c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
- (d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
- (e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. **Punishment and compensation**- (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may,-

- (a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - (b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - (c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - (d) award reformatory punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
- (3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
- (a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - (b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - (c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - (d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - (e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. **Action against frivolous complaint**.—To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)

of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

12. Consequences of non-compliance.—(1) The Commission shall, in respect of any institution that will fully contravene or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice: -

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956;
 - (b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (f) of section 2 of said Act, 1956;
 - (c) withholding any grant allocated to the institution;
 - (d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;
 - (e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;
 - (f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
 - (g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;
 - (h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act;
 - (i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations;
- (2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

[Advt.-III/4/Exty/53]

JASPAL S. SANDHU, Secy, UGC

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
New Delhi**

NOTIFICATION

Dated 01-07-2009

Sub: Prevention and prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

F.No.37-3/Legal/AICTE/2009 – In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education, hereby makes the following Regulations:-

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of the notification.

2. Objectives:-

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295 of 2006 dated 16-05-2007 and in Civil Appeal number 887 of 2009, dated 08-05-2009 to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the All India Council for Technical Education,(AICTE) brings forth these Regulations.

3. Definitions:-

- (a) **“Act”** means the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987);
- (b) **“Technical Institution”** means an institution of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting the courses/programmes in the field of technical education, training and research in Engineering, Technology including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time;
- (c) **“University”** means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution deemed to be a University under section 3 of that Act.
- (d) **“Academic year”** means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
- (e) **“Head of the institution”** means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
- (f) **“Fresher”** means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
- (g) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1887, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1887, as the case may be. And
- (h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

4 **What constitutes Ragging:** - Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, posts, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

5. Measures for prevention of ragging:-

It shall be mandatory for every technical Institution, University, deemed to be University imparting technical education to take following measures for prevention of ragging at such institutions.

1. The advertisement issued for admission by a technical institution, University including Deemed to be University concerned and/or the admission authority/ affiliating University/State Govt./UT/Central Govt. as the case may be, shall clearly mention that ragging is totally banned and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished.
2. The 'Prospectus' and other admission related documents shall contain directions of the Supreme Court Affiliating University/admission Authority/State Govt/Central Govt. shall make it mandatory for the institutions under their jurisdiction to compulsorily incorporate such information in their 'Prospectus'. These Regulations shall be printed in the brochure of admission/instruction booklet for candidates.
3. The application form for admission/enrolment shall have a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages. The affidavit should be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.
4. The application form shall also contain a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages and the affidavit should be signed by the parent/guardian of the applicant to the effect that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
5. The application for admission shall be accompanied by a document along with the School Leaving Certificate/Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon the student who has a negative entry in this regard.
6. A student seeking admission to the hostel shall have to submit another affidavit along with his/her application for hostel accommodation that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishments meted out if he/she is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
7. Every technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall maintain a proper record of the affidavits obtained to ensure its safe up keep thereof, including digital copies of the affidavits and such digital copy should be made available to the AICTE or to an Agency identified/nominated by AICTE.

8. The AICTE or an Agency identified/nominated for the purpose and affiliating Universities and Directorate of Technical Education of the concerned State Govt./UT shall maintain an appropriate data base of the affidavits in the digital form obtained from every student at the time of admission to the technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.
9. Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of staff. Such staff member should interact individually with each member of the group on daily basis to ascertain the problems/difficulties, if any faced by the freshers in the Institution and extend necessary help.
10. Incase of freshers admitted to a Hostel it shall be the responsibility of the teacher incharge of the group to co-ordinate with the warden of the Hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged. Freshers should be lodged in a separate hostel block wherever possible and where such facilities are not available, the college/institution shall ensure that seniors' access to freshers' accommodation is strictly monitored by wardens, Security Guards and Staff.
11. Every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels. At the commencement of the academic session the Head of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.
12. Every fresher admitted to the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall be given a printed information booklet detailing when and whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committee, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc.
13. The technical institutions, University including Deemed to be University imparting technical education through the information booklet mentioned

above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

14. The information booklet mentioned above shall also tell the freshers about their rights as bona fide students and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.
15. The information booklet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of juniors with the academic environment of the institution.
16. To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably with different colors for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.
17. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institutions 's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favor.
18. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall identify, properly illuminate and man all vulnerable locations.
19. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.
20. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, information booklets, seminars, street plays, etc.

21. The faculties/departments/units of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.
 22. Mobile Phones and other communication devices may be permitted in residential areas including hostels to provide access to the students particularly freshers, to reach out for help from teachers, parents and Institution authorities.
6. **Monitoring mechanism in technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education:-**
- a) **Anti-ragging Committee:** Every institution University including Deemed to be University imparting technical education shall constitute a Committee to be known as the Anti-ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the Institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of level as well as gender.
 - b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
 - c) **Anti-Ragging Squad:** Every institution University including Deemed to be University imparting technical education shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
 - d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents and having the potential for ragging and shall be empowered to inspect such places.

- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incidents of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incidents of ragging, and considerations such other relevant information as may be required.
- f) **Mentoring Cell:** Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- g) **Monitoring Cell on Ragging:-** The State Govt./UT and the affiliating University shall set up a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with the institutions to monitor the activities of the Anti-Ragging Committees, Squads, and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions, etc., and regarding the incidents of ragging, the problem faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by such institutions to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of affidavits from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action by the University authorities to suitably amend the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti ragging measures at the level of the institution.
- h) The Monitoring Cell shall coordinate with the the institutions, universities including deemed to be universities imparting technical education to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the Anti-Ragging Committees etc.

- i) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violation; and shall function as the prime mover for initiating action for amending the Statues or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.
- 7. Action to be taken against the Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-Teaching staff of technical institution, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.**
1. The Head of the Institution along with other administrative authorities should take adequate measures for prevention of ragging. Any lapse on the part of these authorities shall make them liable for criminal action for negligence of duty. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should incorporate a clause in their letter of appointment that the Director, Faculty and other administrative Heads should ensure all possible steps for prevention of ragging in the premises of the educational institutions, and that they are liable for action, in case of non-compliance.
 2. The Principal or Head of the Institution/Department shall obtain an affidavit from every employee of the Institution including teaching/non-teaching staff, contract labor employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the building, lawns etc. that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. A provision shall be made in the service rules for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report ragging which will form part of their service records.
 3. Departmental enquiries shall be initiated, in addition to penal consequences against such heads of the Institution/Faculty members/non-teaching staff who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging and would not take timely steps in the prevention of ragging and punishing those who rag.
 4. The Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-Teaching staff, if found negligent in taking necessary measures for ensuring safety of students and preventing the ragging would be declared unfit for holding any post in any technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education.

8. Actions to be taken against students for indulging and abetting ragging in technical institutions Universities including Deemed to be University imparting technical education:-

1. The punishment to be meted out to the persons indulged in ragging has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents.
2. Every single incident of ragging a First Information Report (FIR) must be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities.
3. The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, with regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging.
4. a) Depending upon the nature and gravity of the offence as established the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:-
 - (i) Cancellation of admission
 - (ii) Suspension from attending classes
 - (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
 - (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process
 - (v) Withholding results
 - (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
 - (vii) Suspension/expulsion from the hostel
 - (viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
 - (ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.
 - (x) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.
- b) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

- i. In case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of the University, to the Vice-Chancellor of the University;
 - ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.
 - iii. In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.
5. The institutional authorities shall intimate the incidents of ragging occurred in their premises along with actions taken to the Council from time to time.

9 Action to be taken against the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education which fail to take measures for prevention of ragging:-

1. Role of the concerned technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education shall be open to scrutiny for the purpose of finding out whether they have taken effective steps for preventing ragging and action taken against provision indulged and/or abetting ragging. The Council shall constitute Committees to inspect technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education to verify the status of anti ragging measures and to investigate specific instances of ragging and take appropriate action.
2. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should submit an affidavit along with its compliance report submitted to AICTE annually with details of measures taken for prevention of ragging in technical institutions. The Compliance Report should also contain the details of the instances of ragging and action taken against students, and others for indulging and abetting ragging.
3. All Letters of Approval issued by AICTE such as extension of approval letters, letters issued for additional courses/increase in intake and letters issued for new technical institutions, release of grants, letters of approval issued to integrated campus, second shift etc. shall contain a specific clause of prevention of ragging.
4. The AICTE shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely;

- i. No admission/Withdrawal of approval granted under section 10(k) of AICTE Act.
 - ii. Withholding any grant allocated.
 - iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the AICTE.
 - iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the AICTE, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
 - v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.
5. As regards the Universities including Deemed to be Universities imparting technical education the actions proposed to be taken such as stopping release of grants, withdrawal of approval/recognition will be sent to University Grants Commission (UGC), Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India and the concerned State Govt./UT. The UGC, MHRD Govt. of India, and the State Govt./UT concerned shall initiate immediate action on the recommendations of the Council.

10. Duties and Responsibilities of the All India Council for technical Education:-

- a) All India Council for technical Education, or the Central Government or the agency authorized for the purpose shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
- b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
- c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

- d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti- ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
- f) The All India Council for technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.
- g) The All India Council for technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorized by the All India Council for technical Education/Central Government.

11. The All India Council for technical Education shall take the following regulatory steps, namely;

- a) The All India Council for technical Education shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The All India Council for technical Education shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The All India Council for technical Education shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the All India Council for technical Education, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by National Board of Accreditation or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The All India Council for technical Education shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for technical Education/Central Government and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- f) The All India Council for technical Education shall institute an Anti-Ragging Cell within the AICTE as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cells and University Level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for technical Education/central Government.

(Member Secretary)